CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

CEASI TIMES

हिन्दी

सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR
DAIRY SKILLS IN INDIA

CEFMI
Centre of Excellence for
Farm Mechanization Skills in India

CEHSI
Centre of Excellence for
Horticulture Skills in India

CEASI TIMES

तमिलनाडु के डेयरी किसानों के लिए हेल्पलाइन शुरू

डेयरी विकास मंत्री टी. मनो थंगराज ने घोषणा की कि आविन उपभोक्ताओं और डेयरी किसानों दोनों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका लक्ष्य गुणवत्ता बनाए रखते हुए किसानों को स्थिर आय देना है। इस समय आविन 3.8 लाख किसानों से रोज़ाना 36.50 लाख लीटर दूध खरीदता है और 30.02 लाख लीटर दूध बेचता है। मंत्री ने पिछले 4 वर्षों में दूध खरीद में वृद्धि और शहरी क्षेत्रों में बिक्री बढ़ाने के प्रयासों का ज़िक्र किया।

उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और किसी भी गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर पशुपालन सचिव एन. सुब्बियन और आविन के प्रबंध निदेशक ए. अन्नाथुरई भी मौजूद थे।

किसानों की सहायता के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-425-2577 शुरू की गई है, जिस पर वे पशु चिकित्सकों से सहायता ले सकते हैं। यह सेवा इंडसइंड बैंक लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी भारत फाइनेंशियल इनक्लूजन लिमिटेड (BFIL) द्वारा BFIL के "भारत संजीवनी" कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही है।

सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग: भारत की हरित विकास और ग्रामीण समृद्धि की दिशा में राह

भारत का डेयरी क्षेत्र, जो दुनिया में सबसे बड़ा है, लंबे समय से ग्रामीण आजीविका और देश की पोषण जरूरतों को पूरा करता आ रहा है। 80 मिलियन से ज्यादा ग्रामीण परिवार इससे जुड़े हुए हैं, जिससे यह अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। लेकिन पारंपरिक तरीकों से पर्यावरण, खासकर मीथेन गैस उत्सर्जन और कम उत्पादन को लेकर चिंताएं बढ़ीं।

सरकार की गोबरधन योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसे प्रयासों ने जैविक खाद के बेहतर उपयोग और देशी नस्लों के विकास को बढ़ावा देकर पर्यावरण अनुकूल डेयरी पद्धतियों को प्रोत्साहित किया। तकनीक और प्रशिक्षण के ज़रिए किसानों को सहायता दी गई।

कई कंपनियों और एनजीओ ने यह साबित किया कि टिकाऊ खेती और मुनाफा एक साथ संभव है। जैविक खेती और किसान उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले मॉडल देश के कई हिस्सों में सफल रहे। बायोगैस प्लांट, ऑटोमेशन और डिजिटल टूल्स जैसे नवाचारों से किसानों को कचरा प्रबंधन, उत्सर्जन में कमी और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिली।

आनुवंशिक सुधारों से पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता और दूध उत्पादन में भी सुधार हुआ। अनुसंधान, प्रशिक्षण और बाजार आधारित प्रोत्साहन के साथ, भारत का डेयरी क्षेत्र कृषि क्षेत्र में टिकाऊ बदलाव की दिशा में अग्रणी बन सकता है।

CEASI TIMES

कोल्हापुर में विशेषज्ञों ने टिकाऊ डेयरी खेती में नवाचारों पर की चर्चा

हाल ही में कोल्हापुर में "सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग और नवाचार" पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें पशु चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और डेयरी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान और टिकाऊ तरीकों के ज़रिए भारत के डेयरी क्षेत्र को आगे बढ़ाना था।सेमिनार में पशु कल्याण, पर्यावरणीय प्रभाव और फार्म की दक्षता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। विषयों में नैतिक पशुपालन, तनाव में कमी, टोटल मिक्स्ड राशन (TMR), और बेहतर पोषण व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया। विशेषज्ञों ने छोटे और बड़े डेयरी किसानों के लिए व्यावहारिक और आसानी से अपनाई जा सकने वाली तकनीकों पर जोर दिया। आधुनिक चारा प्रबंधन, गोबर प्रबंधन और ज्ञान साझा करने की जरूरत को टिकाऊ बदलाव की कुंजी बताया गया।कार्यक्रम का मकसद जागरूकता और सहयोग के ज़रिए ऐसी डेयरी पद्धतियों को बढ़ावा देना था, जो पशु कल्याण, किसानों की आजीविका और डेयरी क्षेत्र की दीर्घकालिक मजबूती सुनिश्चित कर सकें।

पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ने डेयरी किसानों के लिए पोषण तकनीकों पर प्रशिक्षण आयोजित किया

गुरु अंगद देव वेटरनरी और एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना के पशु पोषण विभाग द्वारा “डेयरी किसानों के लिए पोषण तकनीकों” पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डेयरी किसानों को आधुनिक पोषण विधियों के बारे में जानकारी देना था, जिससे वे अपने डेयरी व्यवसाय की उत्पादकता और लाभ को बढ़ा सकें। विशेषज्ञों ने स्थानीय संसाधनों के उपयोग से संतुलित आहार देने पर व्यावहारिक प्रदर्शन और व्याख्यान दिए।

कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि सही आहार विधियों से डेयरी फार्मिंग की लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रशिक्षण में मिनरल मिक्सचर, यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक और बाईपास पोषक तत्वों के उपयोग जैसी जानकारियाँ दी गईं। किसानों को साल भर पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने के लिए साइलैज और हे बनाने की तकनीकें भी सिखाई गईं।

यह प्रशिक्षण डेयरी खेती को एक टिकाऊ आजीविका बनाने और ग्रामीण समुदायों को सशक्त करने के प्रयासों का हिस्सा था। साथ ही, किसानों को ऐसी नई तकनीकों के बारे में सीखने का अवसर मिला, जो आर्थिक विकास और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दे सकती हैं।

CEASI TIMES

ओडिशा सरकार एआई तकनीक से किसानों को सशक्त बना रही, उपज बढ़ाने और नुकसान कम करने पर जोर

ओडिशा सरकार अब कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का उपयोग कर रही है ताकि किसानों को सटीक और ताजा जानकारी मिल सके। इसका उद्देश्य फसल का नुकसान कम करना और उत्पादकता बढ़ाना है। इस डिजिटल पहल से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जरूरी कृषि संबंधी जानकारी किसानों तक समय पर पहुँचे, जिससे वे सही समय पर निर्णय ले सकें।

हाल ही में एक प्रस्तुति में बताया गया कि किस तरह एआई का इस्तेमाल भौगोलिक और कृषि से जुड़ा डेटा विश्लेषण करने में किया जा रहा है, जिससे खेती के तरीकों को बेहतर बनाया जा सके। विशेषज्ञों ने दिखाया कि तकनीक की मदद से फसल की बेहतर योजना, संसाधनों का सही प्रबंधन और उपज का अनुमान लगाना आसान हो जाता है, जिससे खेती अधिक टिकाऊ और प्रभावी बनती है।

यह पहल ओडिशा की डिजिटल कृषि की दिशा में बड़े कदम का हिस्सा है, जिससे यह साफ होता है कि राज्य सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक और जानकारी से सशक्त बनाना चाहती है। एआई आधारित समाधान अपनाकर ओडिशा किसानों को आत्मनिर्भर, जागरूक और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार बना रहा है।

हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों में ड्रोन स्टेशन स्थापित होंगे, कृषि और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

हिमाचल प्रदेश सरकार कृषि और बागवानी में आधुनिक तकनीक लाने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग शुरू कर रही है। इसके तहत हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा जिलों में ड्रोन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन स्टेशनों के ज़रिए खेती और बागवानी के कामों को आसान और कारगर बनाने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य एक ऐसा ड्रोन इकोसिस्टम तैयार करना है जो न सिर्फ कृषि के लिए, बल्कि आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी उपयोगी हो।

ड्रोन की मदद से प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी और ज़रूरी दवाइयाँ दूर-दराज़ के इलाकों तक पहुँचाई जा सकेंगी। "ग्रीन हिमाचल" अभियान को आगे बढ़ाते हुए, पूरे राज्य में ड्रोन तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार ड्रोन टैक्सी सेवाएं शुरू करने की भी योजना बना रही है, जिससे किसानों की उपज और ज़रूरी दवाइयाँ जल्दी और सुरक्षित तरीके से दूरस्थ क्षेत्रों में पहुँच सकें।

इस परियोजना में ड्रोन के प्रदर्शन (डेमो), संचालन और रखरखाव के लिए सुविधाएं भी दी जाएंगी, ताकि यह तकनीक हर स्तर पर उपयोग के लिए तैयार रहे। यह कदम राज्य में तकनीकी विकास और किसानों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

CEASI TIMES

औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड कार्यक्रम शुरू करने की सिफारिश

नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में औषधीय पौधों के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए साझेदारी, क्षेत्रीय क्लस्टर और उद्योग से सहयोग पर ज़ोर दिया गया। बैठक में शामिल सरकारी अधिकारियों ने बताया कि भारत में औषधीय पौधों की खेती की बहुत संभावनाएं हैं, जिन्हें अभी तक पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन्होंने घरेलू उत्पादन बढ़ाने, राज्यों के बीच व्यापार को बेहतर करने और निर्यात के नए रास्ते तलाशने की जरूरत पर बल दिया। बैठक में सुझाव दिया गया कि बागवानी योजनाओं के तहत एक मिशन मोड कार्यक्रम शुरू किया जाए, जिससे अच्छी खेती की तकनीकों को अपनाया जा सके और पूरी मूल्य श्रृंखला को मज़बूती मिले। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल, लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाना और एक जैसी दिशा-निर्देश तय करने की बात कही गई। क्षेत्र के अनुसार क्लस्टर बनाना, औषधीय फसलों के लिए विशेष मंडियों की स्थापना और किसानों व उद्योग के बीच साझेदारी को मुख्य रणनीति के रूप में सामने रखा गया। बैठक में यह भी ज़ोर दिया गया कि पौधों से तैयार होने वाले अर्क (extracts) और तेल जैसे उत्पादों का अधिक उत्पादन किया जाए, जिससे खेती को टिकाऊ बनाया जा सके और ग्रामीण आजीविका को भी बढ़ावा मिले।

उत्तर प्रदेश में पहला इंडो-डच बागवानी केंद्र शुरू, उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को मिलेगा बढ़ावा

उत्तर प्रदेश का पहला इंडो-डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हॉर्टिकल्चर बाराबंकी जिले के सोनिकपुर गांव में स्थापित किया गया है। तीन हेक्टेयर में फैले इस केंद्र को लगभग ₹12 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य पूरे राज्य में बागवानी के तरीके को आधुनिक बनाना और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस केंद्र में उन्नत ग्रीनहाउस तकनीक और फसल की कटाई के बाद की प्रोसेसिंग से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं लगाई गई हैं, ताकि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली फसलें उगाने और उन्हें सही तरीके से संजोने में मदद मिल सके। यहाँ मुख्य रूप से टमाटर, रंग-बिरखी शिमला मिर्च, खीरा और फूलों की कई किस्मों की संरक्षित खेती (प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन) पर ध्यान दिया जा रहा है।इसके साथ ही एक बड़ी नर्सरी भी स्थापित की गई है, जो हर चक्र में एक करोड़ पौधे तैयार करने की क्षमता रखती है। इससे राज्य के अलग-अलग जिलों को स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे मिल सकेंगे। केंद्र में किसानों और बागवानी विभाग के अधिकारियों को फसल प्रबंधन, कीट नियंत्रण और निर्यात मानकों की जानकारी देकर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। किसानों और बागवानी विभाग के अधिकारियों को फसल प्रबंधन, कीट नियंत्रण और निर्यात मानकों की जानकारी देकर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

CEASI TIMES

ICRISAT के अध्ययन में पाया गया कि ग्राफ्टिंग तकनीक से टमाटर की उपज में 64% तक बढ़ोतरी हुई

ICRISAT द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में यह सामने आया है कि मजबूत जड़ों वाले पौधों पर टमाटर की ग्राफ्टिंग कर उन्हें नैचुरली वेंटिलेटेड पॉलीहाउस (NVPH) में उगाने से टमाटर की उपज में 64% तक की बढ़ोतरी हुई। खुले खेतों में बिना ग्राफ्ट किए गए पौधों की तुलना में ग्राफ्ट किए गए पौधे ज्यादा ताकतवर साबित हुए, जिनमें बड़े पत्ते और लंबी तुड़ाई अवधि देखी गई। इससे किसानों को 3 से 5 बार अधिक तुड़ाई का मौका मिला।

यह तकनीक न सिर्फ जलवायु के अनुकूल है, बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभदायक साबित हुई। यह पद्धति आजमाई गई सभी विधियों में सबसे ज्यादा आय, लाभ और लागत-लाभ अनुपात देने वाली रही। यह तरीका खासकर छोटे किसानों के लिए मददगार रहा, जो मौसम की अनिश्चितता और मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

आंध्र प्रदेश में चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट्स में टमाटर की उत्पादकता में 30% से लेकर 150% तक की बढ़ोतरी देखी गई। विशेषज्ञों ने इस तकनीक को और अधिक किसानों तक पहुँचाने के लिए प्रशिक्षण, सपोर्ट सिस्टम और बेहतर पौध सामग्री की उपलब्धता को ज़रूरी बताया। यह तकनीक पूरी तरह से गैर-GMO (जनरेटिक रूप से संशोधित नहीं) है और टिकाऊ खेती की दिशा में एक कारगर समाधान मानी जा रही है।

पंचकूला में बागवानी कचरा प्रबंधन, सुरक्षा और आधारभूत ढांचे को मिलेगा बढ़ावा

पंचकूला के इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में पहला बागवानी कचरा निपटान संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ₹2.43 करोड़ की लागत वाले इस प्लांट में गार्डन और बागवानी कचरे को ब्रिकेट्स में बदलने के लिए अत्याधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी। यह परियोजना लैंडफिल में कचरा जाने से रोकने और उसके पुन: उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जो चंडीगढ़ मॉडल पर आधारित है।

करीब 200 सफाई कर्मचारी उपकरणों के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे। घर-घर कचरा संग्रहण और छंटाई की योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

शहर के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए सड़कों पर थर्मोप्लास्टिक पेंटिंग, रिफ्लेक्टर और स्टड लगाए जाएंगे। गांव बुधनपुर में 7 एकड़ भूमि पर नया श्मशान घाट और पार्क बनाया जाएगा।

सुरक्षा और सफाई व्यवस्था के लिए सेक्टर 2 और 4 में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और सफाईकर्मियों की कमी को दूर करने के लिए निजी एजेंसियों की मदद ली जाएगी।

CEASI TIMES

राष्ट्रीय खरीफ अभियान 2025 लॉन्च, भारतीय कृषि को मजबूत करने के लिए कदम

राष्ट्रीय खरीफ अभियान 2025 को नई दिल्ली के भारत रत्न सी. सुब्रमणियम ऑडिटोरियम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में 10 से अधिक राज्यों के कृषि मंत्रियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जबकि अन्य राज्यों के मंत्री वर्चुअली जुड़े। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकार के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र को आगे

बढ़ाना था।मंत्री चौहान ने भारत की बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को बताया और कृषि क्षेत्र में सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और सरकार कृषि विकास, खाद्य उत्पादन और कल्याण योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध है। सम्मेलन में कृषि में लागत घटाने, उत्पादन बढ़ाने और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, चौहान ने 'विकसित भारत संकल्प अभियान' की शुरुआत की, जिसके तहत 16,000 वैज्ञानिक ग्रामीण स्तर पर कृषि जागरूकता फैलाएंगे।

मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद में सुगमता से लाखों किसानों को लाभ

मध्य प्रदेश में इस बार गेहूं की खरीद सीजन बहुत ही शानदार रहा। इस सीजन में पंजीकृत किसानों से 85 लाख मीट्रिक टन (MT) गेहूं की खरीद का अनुमान था। 15 मार्च से शुरू हुआ यह अभियान 4,000 खरीद केंद्रों पर चलाया गया, जहां किसानों को ₹2,600 प्रति क्विंटल की खरीद मूल्य दी गई। मई के पहले सप्ताह तक 76 लाख मीट्रिक टन गेहूं 8.7 लाख से अधिक किसानों से खरीद ली गई थी। किसानों को उनके उत्पाद के बदले ₹16,472 करोड़ का भुगतान किया गया था, और कुल ₹19,400 करोड़ तक का भुगतान किए जाने का अनुमान था। इसके अतिरिक्त, किसानों को ₹1,400 करोड़ का बोनस भी मिलेगा। किसानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिजिटल पंजीकरण और स्थानीय सहायक केंद्रों की व्यवस्था की गई थी। इस प्रक्रिया से किसानों को अपनी उपज को बेचना और भुगतान प्राप्त करना काफी सुविधाजनक हो गया।

मध्य प्रदेश में शरबती और ड्यूरम जैसी उच्च गुणवत्ता वाली गेहूं की किस्में उगाई जाती हैं, जो मालवा पठार के जिलों में प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। इन किस्मों ने राज्य की गेहूं की खरीद और गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

CEASI TIMES

एमएसपी खरीद के लिए बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग अनिवार्य, दालों और तिलहनों की खरीद में बदलाव

कृषि मंत्रालय ने खरीफ 2025-26 सीजन से दालों और तिलहनों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद के लिए बायोमेट्रिक चेहरे की पहचान और पीओएस मशीन के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी खरीद योजनाओं का लाभ केवल असली किसानों को ही मिले, जो पीएम-आशा योजना के तहत आते हैं।

खरीदी अवधि को 60 दिनों तक सीमित किया गया है, जिसे 30 दिन बढ़ाया जा सकता है, ताकि आखिरी समय में कोई गड़बड़ी न हो। नाफेड और एनसीसीएफ जैसी एजेंसियां आधार आधारित पोर्टल्स के जरिए वास्तविक समय में पंजीकरण करेंगी, जो सरकार के एकीकृत कृषि सांख्यिकी प्लेटफॉर्म से जुड़ी होंगी।

खरीदी गई उपज को साल के बाकी 9 महीनों में निपटाया जाएगा। मजबूत फसल संभावनाओं को देखते हुए, सरकार ने 2024-25 सीजन के लिए 6 मिलियन टन तिलहनों और 5 मिलियन टन दालों की रिकॉर्ड खरीद को मंजूरी दी है। नया सिस्टम घरेलू उत्पादन बढ़ाने, आयात को कम करने और किसानों को पीक हार्वेस्टिंग के दौरान MSP से कम बाजार कीमतों पर उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।

हरियाणा ने धैंचा खेती को बढ़ावा देने के लिए ₹1,000 प्रति एकड़ देने की योजना शुरू की

हरियाणा सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को धैंचा (Sesbania bispinosa) की खेती करने पर ₹1,000 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। धैंचा एक हरित खाद फसल है, जो मिट्टी की सेहत और संरचना को सुधारने में मदद करता है। यह नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी को समृद्ध करता है और नमी बनाए रखता है, जिससे सिंथेटिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है और किसानों के लिए लागत भी घटती है।इस योजना के तहत किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस प्रोत्साहन राशि को प्राप्त करने के लिए, किसानों को निर्धारित समय में 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर अपनी फसल की तस्वीरें अपलोड करनी होंगी।

यह पहल स्थायी कृषि और दीर्घकालिक मिट्टी उत्पादकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। योजना का उद्देश्य पूरे राज्य के 22 जिलों में 4 लाख एकड़ भूमि पर फसल विविधता को बढ़ावा देना है, जिसमें 3 लाख से अधिक किसानों के भाग लेने की उम्मीद है। धैंचा को काटने से पहले मिट्टी में मिलाया जाता है, जिससे प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है।

CEASI अपकमिंग एक्टिविटीज

नार्थ-ईस्ट डेरी सम्मेलन – आत्मनिर्भरता की ओर

उत्तर पूर्व डेरी सम्मेलन – आत्मनिर्भरता की ओर, सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI) और असम डेरी विकास निदेशालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन 15 मई, 2025 को असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, खानापारा में होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र में डेरी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

ASCI Agriculture Skill Council of India | CEDSI CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA | सत्यमेव जयते Directorate of Dairy Development Animal Husbandry and Veterinary Department Government of Assam

North East Dairy Conference

Path to Self Sufficiency

Organised by:

Centre of Excellence for Dairy Skills in India

in collaboration with

Directorate of Dairy Development, Assam

Venue: Assam Administrative Staff College, Khanapara

15th May 2025

Supported by:

prompt® The pursuit of purity | ZEUZER INDIA An ISO 9001-2009 Company

Benny Impex® | JUPITOR BENNY GROUP

हम कौन हैं

"सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स (CEASI)" एक स्वायत्त संगठन है, जो "एग्रीकल्चर स्किल कौंसिल ऑफ़ इंडिया (ASCI)" के अधीन कार्य करता है। ASCI, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत काम करता है और इसका उद्देश्य किसानों, श्रमिकों, स्व-रोज़गार करने वाले पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण करना है। यह कार्यक्रम कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए तैयार किया गया है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों का एक शीर्ष संगठन है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेचानिज़शन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEFMI
Centre of Excellence for Farm Mechanization Skills in India

CEHSI
Centre of Excellence for Horticulture Skills in India